

मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 में संशोधन

चर्चा में क्यों?

15 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रपरिषद की बैठक में मंत्रपरिषद ने औद्योगिक नीति नविश प्रोत्साहन विभाग के अधीन विकसित/विकासधीन एवं अविकसित भूमि के उचित एवं कुशल प्रबंधन के लिये नवीन मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 संशोधित करने का निर्णय लिया।

प्रमुख बंदि

- इसमें कंडिका 12(ii) स में औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि/भवन का आवंटन पारदर्शी एवं नष्पिकष रूप से होने के साथ ही राजस्व में बढोत्तरी हो, इसके लिये 'प्रथम आओ प्रथम पाओ' के स्थान पर 'ई-बडिगि' प्रक्रिया का प्रावधान कया गया है।
- कंडिका 12(ii) (द), कंडिका 13(ii) कंडिका 13(III), कंडिका 13(अ) मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित सेवा के अनुसार आशय-पत्र, आवंटन आदेश, पट्टाभलिख नष्पिपादन, आधपित्य आदा की समय-सीमा में संशोधन कया गया है।
- कंडिका 13(vii) चहिनति औद्योगिक क्षेत्रों में रकित भू-खंड के लिये कश्तों में भुगतान करने हेतु प्रावधान कया गया है।
- कंडिका 19(ब) (II) हसतांतरण प्रकरणों में 25 प्रतशित नविश राशा के साथ न्यूनतम राशा 50 करोड रुपए के वकिलप को शामिल कया गया एवं प्रस्तावति परयोजना में कये गए नविश की स्थति अनुसार पृथक्-पृथक् हसतांतरण शुलक का प्रावधान कया गया है।
- कंडिका 20 को पुनरीकषति करते हुए कंडिका 20(अ) एवं 20(ब) कया गया है। कंडिका 20(अ) में कारररत् इकाइयों की अनुपयोगी भूमि के हसतांतरण के लिये न्यूनतम कषेत्फल को 500 वर्गमीटर के स्थान पर 1000 वर्गमीटर एवं कंडिका 20(ब) में बंद इकाइयों की अनुपयोगी भूमि के वभाजन एवं हसतांतरण के लिये प्रावधान कया गया है।
- कंडिका 24(अ) भू-खंड का समरपण कये जाने की स्थति में प्रत्याजी के साथ वकिस शुलक वापसी संबंधी प्रावधान को स्पष्ट करते हुए लघु उद्योग के प्रकरण में 6 वर्ष की समयावधि के बाद तथा मध्यम एवं बृहद् उद्योग के प्रकरण में 7 वर्ष के बाद परंतु 9 वर्ष के पूर्व समरपण करने पश्चात् भी प्रब्याजी राशा वापस करने का प्रावधान कया गया है।
- कंडिका 34 उद्योग अनुषांगिक प्रयोजन के लिये भूमि आवंटन की अधिकारति संचालक मंडल को प्रत्यायोजति की गई है।